



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 520]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1980/कार्तिक 24, 1902

No. 520] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1980/KARTIKA 24, 1902

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

कलकत्ता

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1980

क्र० घा० 892 (घ).—केन्द्रीय सरकार ने, (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 85) की धारा 18-क के अधीन जारी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० घा० 364(घ०), तारीख 29 मई, 1978 द्वारा, प्रसिद्धी संकलन की राज्य सरकार के उद्योग और नव उद्योग विभाग, कलकत्ता को मैसर्स किमीसन जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें आने वाले औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), उसमें विनिश्चित अवधि के लिए, प्रबन्ध प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत किया है।

घटः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18-ड० की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाय प्रवृत्तियों में ऐसे धपकादों, निर्देशनों और सीमाओं को विनिश्चित करती है जिनके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त

औद्योगिक उपक्रम की उम्मीद प्रकट से लागू करने रहेगा जैसे वह धारा 18-क के अधीन प्रवेश के जारी होने से पूर्व लागू था।

प्रवृत्तियों

कम्पनी अधिनियम, 1956 का उपबन्ध	ऐसे धपकाद, निर्देशन और सीमाएं जिनके अधीन संलग्न (1) की उम्मीदित उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। किन्तु वह कम्पनी रजिस्ट्रार के पास लागू की विवरणों और सुझावों को प्रेषित करेगा। इस छूट का प्रभाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों पर नहीं होगा।
धारा 169	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 210 (1)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे किन्तु वह कम्पनी रजिस्ट्रार के

(1)	(2)
	पास कानूनी विवरणियां और तुलन-पत्र फाइल करेगा। इस छूट का प्रभाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों पर नहीं होगा।
धारा 217	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 219	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस धारा के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस धारा के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा 293(1)(ब)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
<p>कभी मामलों में छूट की प्रवधि का, केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन कम्पनी का प्रबन्ध किया जाना समाप्त हो जाने पर, पर्यवेक्षण हो जाएगा।</p> <p>[फा० सं० 3(4)/78 सी०यू०सी०] धार० एन० चोपड़ा, संयुक्त सचिव</p>	

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 15th November, 1980

S.O. 892 (E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 364 (E), dated the 29th May, 1978 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the State Government of West Bengal in the Department of Sick and Close Industries, Calcutta, to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs The Kintison Jute Mills Company Limited, Calcutta, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to

the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking.
(1)	(2)
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210(1)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 219	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 293(1)(d)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

The period of exemption in all cases will terminate when the Company ceases to be managed by the Central Government under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[F. No. 3(4)/78-CUS]
R. N. CHOPRA, Jt. Secy.